(e) and (f) Besides other steps being taken to maximise procurement of wheat for Central Pool under price support scheme, the Government has announced a bonus of Rs. 25 per quintal over and above the minimum support price of wheat payable to the farmers for sale of wheat to FCI/its agencies during the period from 1st April, to 31st May, 1902. In addition to this, a bonus of Rs. 5 per quintal has been declared by the Goverement of Punjab and Haryana and Rs. 25 per quintal by Madhya Pradesh Government.

खाद्यान्नों की जमाखोरी

1413. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों की बड़े पैमाने पर जमाखोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने जमाखोरी के कितने मामले पकड़े हैं और उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितने मूल्य को खाद्यान्न जब्त किया गया, इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में जमाखोरों के विरुद्ध छापे मारे जाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं जो खाद्यान्नों कीजमाखोरी करने और खाद्यान्नों के व्यापार में अन्य कदाचार करने में लिप्त पाए गए। एक विवरण संलग्नहै (नीचे देखिए) जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान जमाखोरी के पकड़े गए मामलों की संख्या और जब्त किए गए जमाशुदा खाद्यान्नों का कुल मूल्य दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों की 7-2-1992 को पुनः लिखा गया है जिसमें प्रभावकारी जमाखोरी निरोधी उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1989, 1990 और 1991 के दौरान जमाखोरी के पकड़े गए मामलों की संख्या और जब्त किए गए जमाशुदा खाद्यान्नों के मूल्य का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	जिन पर मुकदमा चलाया गया, उनकी संख्या	दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए खाद्यान्नों का मूल्य
1	2	3	4	5
				(लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	4020	108	21	861.26
असम	20	80	14	0.28
अरुणाचल प्रदेश	--	--	---	—
बिहार	429	441	—	276.49
गुजरात	85	98	11	304.50
गोआ	7	6	--	2.96
हरियाणा	284	70	—	643
हिमाचल प्रदेश	2	8	1	0.19
जम्मू तथा कश्मीर	441	142	5	1.72

1	2	3	4	5
कर्नाटक	2008	522	3	115.78
केरल	—	15	1	5.10
मध्य प्रदेश	200	712	69	635.35
महाराष्ट्र	2407	1112	223	492.97
मणिपुर	20	—	—	—
मेघालय	—	1	—	—
मिजोरम	10	6	—	0.62
नागालैण्ड		शून्य		
उड़ीसा	65	416	16	67.84
पंजाब	22	36	—	9.68
राजस्थान	117	600	464	71.46
सिक्किम	23	—	—	—
तमिलनाडु	1400	4186	440	546.13
त्रिपुरा	69	45	16	0.89
उत्तर प्रदेश	3016	4587	163	2408.32
पश्चिम बंगाल	3379	1713	32	498.95
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	28	361	1	27.85
चंडीगढ़	—	6	—	—
दादर तथा नगर हवेली	7	—	—	15.29
दिल्ली	285	183	36	9.93
दमन और दीव		शून्य		
लक्षद्वीप		शून्य		
पांडिचेरी	222	122	52	2.08

Sugar mills in Uttar Pradesh

1414. SHRI ASHWANI KUMAR : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) the number of Sugar mills functioning in Uttar Pradesh in (i) Cooperative Sector (ii) Private Sector and (iii) Public Sector ; at present;

(b) what is the percentage of total production of Sugar Cane used for producing Sugar ; and

(c) the measures taken by Government for the full exploitation of Sugar-Cane by these factories ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) There are 104 sugar factories working in Uttar Pradesh in the current 1991-92 season comprising 31 sugar factories in co-operative sector, 42 in private sector and 31 in public sector.

(b) Sugar crushing is still going on for 1991-92 season and the percentage of cane drawn by the sugar factories in Uttar Pradesh can be ascertained only after all the sugar factories close their crushing operations in the current season. However, during the previous 1990-91 season, sugar factories in Uttar Pradesh crushed about 31.6% of the sugar cane produced in Uttar Pradesh.

(c) In order to encourage early crushing and thereby maximise sugarcane utilisation, Government had announced an incentive scheme under which sugar factories were entitled to free-sale quota at 72%, as against the normal 55%, on the entire production achieved during the early crushing period from 1-10-1991 to 15-11-1991.